स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (CCIL) के न्यूज़लेटर्स, जनवरी, 2010

भारित औसत मांग दरें

3.50
3.40
3.30
3.20
3.10

जलाई

इंटरनेशनल फाइनैन्स कार्पोरशन (IFC) जैसी अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कम्पनियों के भारत में स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं का वित्तीयन करने हेतु उत्सुक होने के फलस्वरूप भारतीय स्टेट बैंक ने कार्बन फूटप्रिंट को कम करने में अग्रणी भूमिका निभाने की तत्परता दिखाई है। बैंक ने अपने उपक्रम की शुरूआत कोयम्बतूर (तमिलनाडु) में उसके पहले वात क्षेत्र (wind farm) का उद्घाटन करते हुए की। सुजलान एनर्जी द्वारा आपूर्ति की गई 15 मेगावाट की इस परियोजना में सुजलान की एस-82 वाली 10 इकाइयों तथा 1.5 मेगावाट के विंड टर्बाइन जेनरेटरों का समावेश है। इसके पूर्व इन जेनरेटरों को गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में संस्थापित किया गया था। उक्त परियोजना भारतीय स्टेट बैंक की अपने कार्बन फूटप्रिंट को घटाने तथा ग्राहकों को कार्यकुशल प्रक्रियाएं अपनाने के बारे में संवेदनशील बनाने का एक महत्वपूर्ण अंग है। इन वात टर्बाइनों से उत्पादित बिजली से इन तीनों राज्यों में भारतीय स्टेट बैंक की विविध प्रकार की सुविधाओं एवं परिचालनों को संचालित किया जाएगा।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

प्रतिदेय जमा प्रमाण पत्र

फेडरल डिपोजिट इंश्योरेंस कार्पोरेशन (FDIC) द्वारा बीमित जमा प्रमाण पत्र (CD), जिसमें अन्य प्रकार की नियत-आय वाली प्रतिदेय प्रतिभूतियों जैसी ही विशेषता निहित होती है। प्रतिदेय जमा प्रमाण पत्रों को जारीकर्ता बैंक द्वारा उनकी विनिर्दिष्ट परिपक्वता के पूर्व, सामान्यत: एक निदिष्ट समय-सीमा में तथा वर्तमान मांग मूल्य पर मोचित (वापस लिया) लिया जा सकता है। बैंक जमा प्रमाण पत्र में मांग की विशेषता इसलिए योजित करता है, ताकि ब्याज दरों में कमी हो जाने पर उसे जमा प्रमाण पत्र धारक को उच्चतर दर का भुगतान जारी न रखना पड़े। प्रतिदेय जमा प्रमाण पत्रों को निवेशकों को मांग जोखिम उठाने के लिए प्रोत्साहन के रूप में प्राय: उनके क्रय मूल्य की तुलना में अधिमूल्य पर मोचित किया जाता है।

भारत के समाचार पत्र पंजीकार (रजिस्ट्रार) के पास संख्या : 69228 / 98 के अधीन पंजीकृत

- पंजीकरण संख्या : एमएच / एमआर / दक्षिण -42 / 2010 -12
  पूर्व-अदायगी के बिना प्रेषित करने का लाइसेंस संख्या 15 / दक्षिण / 2010 -

- मुंबई पत्रिका चैनल छंटाई कार्यालय मुंबई - 1 पर प्रत्येक महीने की 25वीं और 26वीं तारीख को प्रेषित करें।

शब्दावली

प्रतिभूतिकरण

प्रतिभूतिकरण एक संस्था / कम्पनी द्वारा उसके ऋण संविभाग के एक अंश का दूसरी कम्पनी को बेचना होता है। तकनीकी रूप से यह ऋणों को ऐसे मानक विक्रेय बॉण्डों में एक साथ समूहित करना है, जिसका उपयोग आगे चल कर उसके उधार देने के कारबार हेतु किया जा सके। एक बार परिवर्तित कर लिए जाने पर ये ऋण बैंक की आस्तियां नहीं रह जाते, यद्यपि बैंक निवेशकों के लिए ऋण का भुगतान करना जारी रख सकता हैं।

प्रावधान व्याप्ति अनुपात

बैंक की आस्ति गुणवत्ता का विश्लेषण करने में एक विशिष्ट तिथि को बैंक के संचित प्रावधान की शेष राशियों का मुख्य सम्बन्ध सकल अनर्जक आस्तियों के साथ होता है। प्रावधान व्याप्ति अनुपात से आशय है ऋण की रकम का वह प्रतिशत, जो बैंक ने किसी ऐसी घटना का सामना करने हेतु अलग रख छोड़ा है, जिसमें ऋण को बट्टे खाते डालना पड़े। अधिक अनुपात इस बात का संकेत करता है कि आगामी वर्षों में बैंक द्वारा किए जाने वाले अतिरिक्त प्रावधान (सकल अनर्जक आस्तियों के तेजी से न बढ़ने पर) अपेक्षाकृत कम होंगे।

संस्थान समाचार

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए जोखिम आसूचना पर विशेष कार्यक्रम

संस्थान द्वारा डेलॉइट के सहयोग से अप्रैल माह के दौरान सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए जोखिम आसूचना पर एक कार्यक्रम अयोजित किया गया, जिसमें 5 महा प्रबन्धकों और 9 उप महा प्रबन्धकों ने सहभागिता की। उक्त कार्यक्रम ने बैंकों के समक्ष उपस्थित होने वाले विविध प्रकार के जोखिमों के प्रति अन्तर्दृष्टि प्रदान की।

महत्वपूर्ण दरें / अनुपात

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूज़लेटर प्रतिवर्ष 40/रुपये

(आईएसओ 9001 : 2000 प्रमाणित संगठन)

आईआईबीएफ विज़न

व्यावसायिक उत्कृष्टता
के प्रति प्रतिबद्ध

खंड सं. : 2 अंक सं. : 11 जून 2010

संस्थान (इंस्टिट्यूट) का ध्येय (मिशन) "प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श / सलाह और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से व्यावसायिक रूप से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना है।"

सीएआईआईबी परीक्षा से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना (**पृष्ठ सं. 8 देखें**)

विषय-सूची

मुख्य घटनाएं---------- 1
केन्द्रीय बैंकिंग----------2
बैंकिंग जगत की घटनाएं----------3
विनियामकों के कथन ----------4
विदेशी मुद्रा----------4
जिंस बाज़ार----------4
पूंजी बाज़ार----------5
पारस्परिक निधियां----------5
बीमा----------5
अंतरराष्ट्रीय समाचार----------5
विशिष्ट घटनाएं----------6
नयी नियुक्तियां----------6
उत्पाद एवं गंठजोड----------6
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारीं ---------- 7
शब्दावली ----------7
बाज़ार की खबरें----------7
संस्थान समाचार----------8

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों / मीडिया में प्रकाशित हो चुकी / चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की / किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना / समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित / उल्लिखित घटनाएं सम्बन्धित स्रोत द्वारा यथा अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों / घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सूचना की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी प्रकार से न तो उत्तरदायी है न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएं

आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ राजस्थान के निदेशक मण्डलों ने विलयन प्रस्ताव को मंजूरी दी

आईसीआईसीआई बैंक और बैंक ऑफ राजस्थान (BoR) के निदेशक मण्डलों ने दोनों के बीच विलयन प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है; शेयरधारकों का अनुमोदन 21 जून को आयोजित होने वाली असाधारण सभा (EGM) में प्राप्त किया जाएगा। यह किसी पुराने निजी क्षेत्र के बैंक का आईसीआईसीआई बैंक द्वारा तीसरा अभिग्रहण होगा।

सरकारी बैंकों का विवाचन ग्रामीण अभियान द्वारा किया जाएगा

अब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) को अल्पसुविधाप्राप्त लोगों को बैंकिंग की परिधि में लाने के उद्देश्य से अधिक नो फ्रिल्स खाते खोलने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त होंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कार्य-निष्पादन का विवाचन करने हेतु प्रयुक्त होने वाले विविध मापदंडों में इस वर्ष सरकार ने 'वित्तीय समावेशन' को भी जोड़ दिया है। अब तक ये मापदंड व्यापक रूप से बैंक की वित्तीय स्थिति और अर्थव्यवस्था अर्थात् निवल लाभ, अग्रिमों में वृद्धि, अल्प-लागत वाली जमाराशियों की वृद्धि, अशोध्य ऋणों में गिरावट आदि से सम्बन्धित हुआ करते थे। इस नयी स्थिति को ध्यान में रखते हुए अब बैंकों को उनके द्वारा समाविष्ट किए जाने वाले गांवों की संख्या तथा इस वित्त वर्ष में उनके द्वारा खोले जाने वाले नो फ्रिल्स खातों की संख्या का उल्लेख करना होगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय रूप से सुदृढ़ सहकारी बैंकों को एटीएम खोलने की अनुमति दी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सुदृढ़ कारपोरेट अभिशासन वाले वित्तीय रूप से सुदृढ़ शहरी सहकारी बैंकों (USBs) के मामले में शाखेतर एटीएम लगाने से सम्बन्धित अपने नियमों को शिथिल कर दिया है। अबसे, अपेक्षाकृत कम स्तर के अशोध्य ऋणों वाले, निरंतर तीन वर्षों से लाभार्जन करने वाले तथा उनके निदेशक मण्डलों में व्यावसायिकों की मौजूदगी वाले बैंकों को शाखेतर एटीएम लगाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। तदनुसार, बैंकों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे

अनुमोदन के बिना एटीएम लगाने का पात्र बनने के लिए अपनी निवल अनर्जक आस्तियों (NNPAs) को 5 % से कम पर नियंत्रित रखें तथा अपने निदेशक मण्डल में कम से कम दो व्यावसायिकों का समावेश करें। अपनी आरक्षित नकदी निधि अनुपात (CRR) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (SLR) से सम्बन्धित अपेक्षा का पालन करने में कभी भी चूक करने वाले अथवा पिछले वर्ष में उसका पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CAR) घट कर 10 % से कम हो जाने वाले बैंक को अयोग्य ठहरा दिया जाएगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 926 शाखाओं को अग्रिम आय कर स्वीकार करने की अनुमति प्रदान की

आय कर निर्धारितियों को सुविधा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने मुंबई और नई मुंबई में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों की 926 शाखाओं को अग्रिम आय कर वसूल करने की अनुमति प्रदान की है। अब तक केवल भारतीय रिज़र्व बैंक ही अग्रिम आय कर वसूल किया करता था। इन 826 शाखाओं में से 862 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से, 35 एचएफडीसी बैंक से, 10 आईसीआईसीआई बैंक से और 15 ऐक्सिस बैंक से सम्बन्धित हैं। कई एक कारपोरेट गृहों का मुख्यालय होने के कारण मुंबई को अग्रिम आय कर का सबसे अधिक हिस्सा प्राप्त होता है।

बैंक ऋणों में 13,030 करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी

ऋण की मांग में स्थिर वृद्धि का संकेत करते हुए 7 मई 2010 को समाप्त पखवाड़े के दौरान बैंक ऋण 13,030 करोड़ रुपये की वृद्धि के साथ 32,27,771 करोड़ के स्तर पर पहुंच गए। वर्षानुवर्ष आधार पर ऋण में 17.25 % की वृद्धि दर्ज हुई। कृषि अवप्राप्ति में, विनिर्माण क्षेत्र की मांग के अनुरूप ही वृद्धि हो रही है। अतएव, स्वीकृत ऋणों से आहरण बढ़ रहे हैं। मंदी -रहित समय, जब प्रारंभिक महीनों में ऋणों का कम उठाव परिलक्षित होता है, के विपरीत ऋणों के उठाव में 1ली तिमाही में और भी वृद्धि होने की आशा है।

इंडिया इंक निधि प्रवाह के लिए वाणिज्यिक पत्रों पर अधिक निर्भर

इंडिया इंक निधीयन के लिए बैंकेतर स्रोतों पर अधिकाधिक निर्भर करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के आंकड़ों के एक विश्लेषण के अनुसार वित्तीय वर्ष 08 में बैंक निधियों का अंश 56.99 % से घट कर वित्तीय वर्ष 10 में 48.8 % हो गया। कारपोरेट कम्पनियां इक्विटियों के सार्वजनिक निर्गम, निजी नियोजनों, कारपोरेट बॉण्डों, विदेशी वाणिज्यिक उधारों (ECBs) और विदेशी प्रत्यक्ष निवेशों (FDI) के माध्यम से भी निधियां जुटाती हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि कारपोरेटों ने वाणिज्यिक पत्रों (CPs), जो बॉण्डों और इक्विटियों के निजी नियोजन के अलावा अब बैंकेतर निधीयन के एक अतिरिक्त स्रोत बन गए हैं, पर अपनी निर्भरता बढ़ा ली है।

केन्द्रीय बैंकिंग नीतियां एवं बैंकिंग जगत की घटनाएं

भारतीय रिज़र्व बैंक ने उधारकर्ता विशिष्ट आधार दर से सम्बन्धित बैंकों का प्रस्ताव ठुकराया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने उधारकर्ता विशिष्ट आधार दर लागू करने से सम्बन्धित कुछेक बैंकों के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया है। उसने उन्हें ब्याज दरों की गणना करते समय नकारात्मक प्रीमियम प्रभारित करने की अनुमति भी नहीं दी है, क्योंकि इसका अर्थ आधार दर से कम पर उधार देना हो सकता था। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई बैंक आधार दर नियत करने हेतु न्यूनतम स्तर के रूप में एक वर्षीय जमाराशियों की सीमान्त लागत का उपयोग करता है, तो नकारात्मक प्रीमियम 12 माह से कम अवधि वाले सभी ऋणों पर प्रभारित किया जाएगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आधारभूत सुविधा वित्तीयन करने वाली कम्पनियों से सम्बन्धित विदेशी वाणिज्यिक उधार नीति को शिथिल बनाया

मुख्य (core) क्षेत्र के सहज वित्तीयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक ने आधारभूत सुविधा वित्तीयन कम्पनियों (IFCs) और केन्द्रीय बैंक द्वारा आधारभूत सुविधा वित्तीयन कम्पनियों के रूप में श्रेणीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों (NBFCs) की तुलना में वर्तमान विदेशी वाणिज्यिक उधार नीति को आशोधित करने का निर्णय किया है। इस प्रकार अब आधारभूत सुविधा वित्तीयन कम्पनियों को उनके द्वारा पहले से लागू विवेकसम्मत दिशानिर्देशों का पालन किए जाने की शर्त पर अपने लिए अनुमोदन मार्ग के अधीन अपनी स्वाधिकृत निधियों के 50 % तक विदेशी वाणिज्यिक उधार (बकाया सहित) प्राप्त करने की अनुमति होगी। आधारभूत सुविधा वित्तीयन कम्पनियों द्वारा उनकी अपनी स्वाधिकृत निधियों के 50 % से अधिक के विदेशी वाणिज्यिक उधारों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का अनुमोदन आवश्यक होगा और इसलिए उसे अनुमोदन मार्ग के तहत माना जाएगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक प्रत्यावर्ती पुनर्खरीद पटल में निधियों में गिरावट : बैंकरों द्वारा दरों में वृद्धि की आशा

घटती चलनिधि की स्थिति इस तथ्य से स्पष्ट हो जाती है कि बैंकों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रत्यावर्ती पुनर्खरीद (reverse repo) पटल में निधियां रखे जाने के स्तर में हाल के दिनों में पर्याप्त रूप से गिरावट आई है। बैंकों द्वारा उसकी चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) के तहत रखे जाने वाले धन की रकम पिछले दो महीनों में 75,000 - 1,30,000 करोड़ रुपये के औसत से घट कर पिछले दो सप्ताहों के दौरान 30,000 - 50,000 के औसत पर आ गई है। एचएसबीसी बैंक के ग्लोबल मार्केट के प्रधान श्री हितेन्द्र दवे का कहना है, आरक्षित नकदी निधि अनुपात में हुई हाल की वृद्धि ने प्रणाली से चलनिधि अवशोषित कर लिया है। हालांकि वह इस समय सहज लग रही है। हम चलनिधि समायोजन सुविधा के अभिदानों के जून तक 30,000 - 50,000 रुपये के बीच स्थिर रहने की आशा कर सकते हैं।

चलनिधि की स्थिति सहज, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अग्र-क्रय उपाय तेज किए

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उधारदाताओं को एक नये पटल के माध्यम से उससे अधिक उधार लेने की अनुमति दिए जाने के बावजूद बैंकरों को 3 जी लाइसेंस के भारी शुल्क तथा अग्रिम कर भुगतान के कारण 1 लाख करोड़ रुपये के अपेक्षित नकदी परिव्यय के परिप्रेक्ष्य में अत्यधिक चलनिधि दबाव की संभावना नहीं दिखाई देती। भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य वित्त अधिकारी श्री एस.एस. रंजन का कहना है, 'यह किसी अनुभूत चलनिधि दबाव को कम करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किया जाने वाला अग्र-क्रय उपाय है।" भारतीय साख-निर्धारण सूचना सेवा लिमिटेड (CRISIL) के प्रधान अर्थशास्त्री श्री डी.के. जोशी ने मत व्यक्त किया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए उपायों का उद्देश्य चलनिधि को कम करना था, यद्यपि बैंकों पर अधिक दबाव नहीं पड़ेगा। हालांकि, बैंक ऑफ बड़ौदा (Bob) के कार्यपालक निदेशक श्री आर.के. बक्शी का कहना है बैंकों को चलनिधि के दबाव का सामना 3 जी स्पेक्ट्रम लाइसेंस के भारी शुल्को और सरकार को अग्रिम कर भुगतान के कारण करना पड़ रहा है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने रुपये को वैश्विक मुद्रा बनाने का मुद्दा उठाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने रुपये को एक वैश्विक मुद्रा बनाने के विचार की पैरवी की है, किन्तु यह मामला केवल सरकार द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई से जुड़े लाभों एवं हानियों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन कर लिए जाने के बाद ही आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि इससे विदेशी मुद्रा विनिमय बाज़ारों में अस्थिरता बढ़ सकती है। इस विचार की पैरवी वैश्विक वित्तीय संकट के बाद की गई थी और कमजोर पड़ते अमरीकी डालर ने एक वैकल्पिक वैश्विक मुद्रा के बारे में बहस ही छेड़ दी। हालांकि, 'इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ करेंसी : दि केस ऑफ दि इंडियन रूपी एण्ड दि चाइनीज़ रेनमिन्बी' शीर्षक वाले अध्ययन मे भी इसकी संभावना नहीं व्यक्त की गई है कि निकट भविष्य में वैश्विक आरक्षित निधि (Reserve) मुद्रा के रूप में डालर अपना प्रभुत्व खो देगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सरहद-पार वाले लेनदेनों से सम्बन्धित मानदंड कठोर किए

किसी भारतीय कम्पनी द्वारा किसी अनिवासी कम्पनी और उसके विपरीत क्रम में विदेशी प्रत्यक्ष मार्ग के अधीन इक्विटी शेयरों की बिक्री से सम्बन्धित मूल्य-निर्धारण मानदंड भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आशोधित कर दिए गए हैं। तदनुसार अब किसी निवासी कम्पनी द्वारा शेयर बाज़ार की सूची में शामिल किसी कम्पनी के शेयरों को किसी अनिवासी को बेचते समय हस्तांतरित शेयरों की कीमत उस मूल्य से कम नहीं होनी चाहिए, जिस पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के दिशानिर्देशों के तहत शेयरों का अधिमानी आबंटन किया जा सकता हो। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के दिशानिर्देशों के अनुसार अधिमानी आधार पर शेयरों का निर्गम ऐसी कीमत पर किया जा सकता है, जो छ: माह की अवधि में अंतिम मूल्य के औसत साप्ताहिक अधिक एवं कम मूल्य अथवा दो सप्ताहों की अवधि के अंतिम मूल्य के औसत से अधिक या कम मूल्य, इनमे से जो भी अधिक हो से कम न हो। पूर्ववर्ती दिशानिर्देशों के तहत निवासी शेयरों को अनिवासियों को ऐसे मूल्य पर हस्तांरित कर सकते थे, जो शेयर बाज़ार में उद्धृत वर्तमान बाज़ार मूल्य से कम न हो।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने मुद्रा अधिप्रमाणन और उपयुक्तता मानदंड जारी किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने नोट अधिप्रमाणन और उपयुक्तता छंटाई सम्बन्धी मापदंडों को अंतिम रूप दे दिया है। इन दिशानिर्देशों को तात्कालिक प्रभाव से कार्यान्वित किया जा सकता है। जहां तक अधिप्रमाणन की जांच का सम्बन्ध है, भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा है कि प्राधिकृत मशीनें अधिप्रमाणन की जांच उसके द्वारा समय-समय पर यथा प्रकटित वास्तविक नोटों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए करेंगी। वास्तविक नोट की सारी विशेषताएं न रखने वाले किसी भी नोट को मशीन द्वारा संदेहास्पद नोट के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

चालू खाते का उदारीकरण :

- भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा है कि बैंक अब अपने ग्राहकों को रायल्टी का भुगतान करने तथा तकनीकी सहयोग के तहत एकमुश्त रकम का भुगतान करने हेतु विदेशी मुद्रा का आहरण वाणिज्य मंत्रालय के अनुमोदन के बिना ही कर सकते हैं। इसके पूर्व, रायल्टी का भुगतान स्थानीय बिक्री के 5 % और निर्यात के 8 % से अधिक होने तथा एकमुश्त भुगतान के 2 मिलियन डालर से अधिक होने वाले मामलों में विदेशी मुद्रा के आहरण के लिए मंत्रालय का अनुमोदन आवश्यक हुआ करता था।

- अब प्राधिकृत व्यापारियों को जारी की जाने वाली समग्र विदेशी मुद्रा में से 3000 अमरीकी डालर या उसके समकक्ष मूल्य के विदेशी मुद्रा नोट एवं सिक्के बेचने की अनुमति है।

- ऐसा विदेशी नागरिक, जो किसी विदेशी कम्पनी का कर्मचारी होने की हैसियत से भारत में रहता हो अथवा ऐसा भारतीय नागरिक, जो भारत से बाहर नियोजित हो, के मामले में भारत से बाहर वाले बैंक में विदेशी मुद्रा खाते में वेतन जमा करने की सीमा 75 % से बढ़ा कर 100 % कर दी गई है।

बैंकिंग जगत की घटनाएं

राष्ट्रीय आवास बैंक की प्रत्यावर्ती बंधक योजना को सीमित प्रतिसाद

राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) द्वारा आरंभ की गई प्रत्यावर्ती बंधक योजना के प्रति आश्चर्यजनक रूप में सीमित रुचि प्रदर्शित हुई है। भारतीय रिज़र्व बैंक के महा प्रबन्धक श्री के.आर. दास ने बताया, "अब तक केवल 7,029 वरिष्ठ नागरिकों ने ही ऋण प्राप्त किया है और सितम्बर, 2008 से 31 मार्च 2010 के दिन तक 1,408 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।" लगभग 23 बैंक प्रत्यावर्ती बंधक ऋण उत्पाद प्रदान करते हैं।

भारतीय निर्यात संगठन महासंघ अध्यक्ष ने स्थिर विनिमय दर की पैरवी की

भारतीय निर्यात संगठन महासंघ (FIEO) ने रुपये की उसके महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदारों यूरोपीय संघ और अमरीका की मुद्राओं के समक्ष अस्थिरता और इस प्रकार निर्यातकों के अर्जन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने पर चिंता व्यक्त की है। भारतीय निर्यात संगठन महासंघ के अधयक्ष श्री ए. शक्तिवेल यह महसूस करते हैं कि भारत को भी उसके प्रतिस्पर्धियों, चीन और बांग्लादेश की भांति ही प्रायोगिक आधार पर कम से कम एक वर्ष के लिए अमरीकी डालर के साथ एक नियत (स्थिर) विनिमय दर व्यवस्था लागू करनी चाहिए, ताकि परिचालन के अल्प-पुनरुत्थान की स्थिति का सामना कर रहे निर्यातकों को कुछ राहत मिल सके। अमरीकी डालर के साथ स्थिर समता दर भारत के लिए सहायक होगी, क्योंकि यूरो रुपये के समक्ष कमजोर पड़ गया है, जिससे यूरो में भुगतान प्राप्त करने वाले निर्यातकों को हानि उठानी पड़ रही है।

विशेष आवास दर के बाद भारतीय स्टेट बैंक ने अपने कृषि ऋण सस्ते किए

देश के सबसे बड़े उधारदाता भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने एक ऐसी योजना को पुनर्जीवित किया है, जिसमें किसानों को सिंचाई और फसल ऋण सस्ती दरों पर उपलब्ध होते हैं। इस रियायत का उद्देश्य आगामी खरीफ मौसम और उसके बाद रबी के मौसम में किसानों की सहायता करना है। भारतीय स्टेट बैंक ने उस विशेष योजना के लिए अपनी उधार दरों को सीमान्त रूप से बढ़ा दिया है, जो पिछले वर्ष कमजोर मानसून और सूखे की स्थितियों से प्रभावित किसानों की सहायता करने के लिए लागू की गई थी। यह बैंक की निधि लागत के कारण किया गया है, जो इस अवधि में बढ़ गई है। हालांकि ये दरें सामान्य अस्थिर दरों की अपेक्षा कमतर ही होंगी।

दीर्घावधिक ऋणों को प्रतिरक्षित करने हेतु ब्याज दर अदला-बदली का प्रयोग करें

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंकों द्वारा प्रतिभूतिकरण से सम्बन्धित मानदंडों को सरल बनाने हेतु प्रस्तुत एक प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक का कहना है कि प्रवर्तक को प्रतिभूत कागज़ातों को कम से कम नौ महीनों तक धारित करना चाहिए तथा उसे प्रतिभूत रकम का कम से कम 5 % उसकी बहियों में प्रतिधारित किए रहना चाहिए। अक्तूबर, 2009 में भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बात का संकेत दिया था कि वह प्रतिभूतिकरण सम्बन्धी मानदंडों को कठोर बनाएगा, जिसके बाद वर्ष 2009-10 में पिछले वर्ष के मुकाबले परिमाण में 22 % संकुचन आ गया था।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा मार्जिन बढ़ाने के लिए वैयक्तिक ऋणों पर ध्यान संकेन्द्रण में तेजी

आर्थिक वृद्धि की गति में तेजी और नौकरी बाज़ार में बढ़ोत्तरी के बीच सार्वजनिक क्षेत्र के कई एक बैंक ब्याज दर मार्जिन और लाभप्रदता बढ़ाने के लिए एक बार पुन: वैयक्तिक ऋणों के माध्यम से ग्राहकों को लुभाने की योजना बना रहे हैं। इनमें से कई एक बैंकों ने आर्थिक मंदी के बाद चूक के भय से वैयक्तिक ऋण उत्पाद प्रदान करना बंद कर दिया था। सामान्यतया किसी अन्य ऋण उत्पाद की तुलना में वैयक्तिक

ऋण अधिक प्रतिलाभ दिलाते हैं। इलाहाबाद बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया जैसे सभी बैंकों ने उनके अधिक प्रतिफल दिलाने वाले वैयक्तिक ऋणों को खुदरा ग्राहकों को बेचने के लिए रणनीतियां तैयार कर रखी हैं। इन वैंकों का खुदरा ऋण अंश विशिष्ट रूप से उद्योग के औसत से कम विशिष्ट रूप से उद्योग के औसत से कम (उद्योग के 20-22 % के औसत की तुलना में लगभग 12-14 %) है।

वर्ष 2009-10 में वाणिज्यक पत्रों में बैंकों का निवेश 25 % अधिक रहा

बैंकों द्वारा वाणिज्यिक पत्रों (CPs) में किए गए कुल निवेश में लगभग 25 % की वृद्धि हुई तथा वह वर्ष 2008-09 के 20,001 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2009-10 में 24,874 करोड़ रुपये हो गया। वाणिज्यिक पत्रों में निवेशों में यह बढ़ोत्तरी कम्पनियों द्वारा कम दरों से अभिलाभ प्राप्त करने हेतु समूहबद्ध होने के परिणामस्वरूप हुई, क्योंकि विश्वव्यापी वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मुख्य दरों में पर्याप्त कमी कर दिए जाने के बाद समग्र दरों में अपेक्षा के अनुरूप कमी नहीं आई। बैंक ऑफ इंडिया (BoI) के कार्यपालक निदेशक श्री नरेन्द्र का कहना है कि बाज़ार में जब तक पर्याप्त चलनिधि मौजूद है तथा उच्चतम श्रेणी वाली कम्पनियों को सस्ती लागत पर निधियों की आवश्यकता है, वाणिज्यिक पत्रों का बाज़ार निरंतर फलता-फूलता रहेगा। यहां तक कि 1 जुलाई, 2010 से आधार दर प्रणाली लागू हो जाने के बाद भी वाणिज्यिक पत्र बेहतर मूल्य-निर्धारण की तलाश में रहने वाले कई एक कारपोरेटों को पूर्ववत आकर्षित करते रहेंगे।

पंजाब नैशनल बैंक ने विदेशी बाज़ारों पर ध्यान केन्द्रित किया

पंजाब नैशनल बैंक विदेशों में अधिक शाखाएं और प्रतिनिधि कार्यालय खोलते हुए अपनी विश्वव्यापी उपस्थिति को और व्यापक बनाने के अवसरों की आक्रामक रूप से प्रतीक्षा कर रहा है। उक्त बैंक इस वित्त वर्ष के दौरान सिडनी आस्ट्रेलिया में अपना प्रतिनिधि कार्यालय तथा कनाडा और नार्वे में शाखाएं खोलने वाला है। इसने काबुल, दुबई और हांगकांग में शाखाएं तथा अलमैटी, दुबई, शंघाई और ओस्लो में प्रतिनिधि कार्यालय खोलते हुए नौ देशों में अपनी उपस्थिति पहले ही दर्ज करा रखी है।

विनियामकों के कथन

पूंजीगत खाते की परिवर्तनीयता के लिए नयी रूपरेखा शीघ्र ही

पूर्ववर्ती दो रिपोर्टों में निर्धारित समय-सारणी को वित्तीय संकट के अनुसरण में परित्यक्त कर दिए जाने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पूंजीगत खाते की परिवर्तनीयता को लागू करने हेतु तीसरी रूपरेखा जारी किए जाने की संभावना है। गवर्नर ने यह भी संकेत किया कि व्यापारिक भागीदारों अथवा प्रतिस्पर्धियों

(यथा-चीन) द्वारा स्थिर दर अंगीकृत किए जाने पर अस्थिर विनिमय दरें भारत के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. डी. सुब्बाराव ने कहा, "हम अपने पूंजीगत खाते को उदारीकृत करने की दिशा में आगे बढ़ने का क्रम जारी रखेंगे, किन्तु हम संकट से लिए गए सबक को प्रतिबिंबित करने के लिए रूपरेखा पर पुनर्विचार करेंगे।" उन्होंने यह भी कहा कि "अर्थव्यवस्था को घरेलू और वैश्विक घटनाओं के प्रत्युत्तर में पुन: अंशाकित (recalibrated) क्रमिक पथ के साथ-साथ पूंजीगत परिवर्तनीयता वाले अनुप्रस्थ मार्ग पर गतिशील आधार पर बढ़ना होगा।" गवर्नर द्वारा की गई उक्त टिप्पणियां उस समय महत्वपूर्ण हो जाती हैं, जब देश डालर की बाढ़ का सामना कर रहा हो, क्योंकि उसके कारण उसे सुदृढ़ रुपये को नियंत्रित करना पड़ता है, जो पुन: निर्यातकों के हित को हानि पहुंचाता है। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि वित्तीय वर्ष 10 में रुपये में सामान्य रूप से 13 % की मूल्यवृद्धि हुई थी, किन्तु भारत और उसके व्यापारिक भागीदारों के बीच मुद्रास्फीति सम्बन्धी अंतर के कारण वास्तविक दृष्टि से यह वृद्धि 19 % थी। इसके फलस्वरूप भारत की विदेशी प्रतिस्पर्धात्मकता ऐसे समय में प्रभावित हुई, जब वैश्विक व्यापार में पुनरुत्थान हो रहा है और संरक्षण से सम्बन्धित चिंताएं पुन: सिर उठा रही हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक स्पंदनशील बॉण्ड बाज़ार की रूपरेखा तैयार करेगा

सरकार और वित्तीय क्षेत्र के विनियामक अंतत: कारपोरेट बॉण्ड बाज़ार में सुधार लाने और उसका विकास करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। विनियामकों और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के समावेश वाली वित्तीय बाज़ारों पर उच्च-स्तरीय समन्वय समिति (HLCCFM) ने कई एक वर्षों से निर्माणाधीन बहुधा प्रस्तावित इन सुधारों से सम्बन्धित एक कार्यक्रम पर विचार-विमर्श किया है। अब भारतीय रिज़र्व बैंक वित्तीय बाज़ारों पर उच्च-स्तरीय समन्वय समिति को एक कार्यपरक दस्तावेज़ प्रस्तुत करेगा, किन्तु उसके लिए कोई समय-सीमा नहीं निर्धारित की गई है। उक्त दस्तावेज़ में कई एक विशेषज्ञ समितियों द्वारा उठाए गए मुद्दों का निराकरण किया जाएगा। जहां राज्य सरकारों द्वारा स्टाम्प शुल्क में कमी किए जाने का प्राय: एक बड़ी रुकावट के रूप में उल्लेख किया जाता है, वहीं विशेषज्ञ समितियों ने अन्य अड़चनों की भी पहचान कर रखी है।

पूंजी सम्बन्धी आवश्यकताओं का आकलन आंतरिक श्रेणी-निर्धारण के आधार पर करें : भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों निर्देश

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वे उन्नत आंतरिक श्रेणी-निर्धारण-आधारित (AIRB) दृष्टिकोण - किसी बैंक की पूंजी सम्बन्धी आवश्यकता का आकलन करने हेतु एक नयी प्रणाली - के लिए तैयार रहें। अब तक बैंक मानकीकृत दृष्टिकोण अपनाते आ रहे हैं, जिसमें वे आस्ति में निहित जोखिम बाहरी साख श्रेणी-निर्धारण एजेन्सियों द्वारा दी गई रेटिंग के आधार पर समनुदेशित करते हैं। सभी बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे न्यूनतम 9 % का पूंजी पर्याप्तता अनुपात बनाए रखें और इसलिए पूंजी का आकलन करने हेतु बैंकों द्वारा अपनाया जाने वाला मॉडेल महत्वपूर्ण होता है। अधिकांश बैंक हर समय 12 % का पूंजी पर्याप्तता अनुपात धारित करने को तरज़ीह देते हैं, क्योंकि कमतर पूंजी पर्याप्तता अनुपात से उनकी संसाधन लागत

बढ़ जाती है। उन्नत आंतरिक श्रेणी-निर्धारण-आधारित दृष्टिकोण बैंकों को बासेल -II का पालन करने वाली संस्था की श्रेणी के एक कदम और निकट पहुंचा देता है। हालांकि, केवल वही संस्थाएं उन्नत आंतरिक श्रेणी-निर्धारण-आधारित दृष्टिकोण कार्यान्वित कर सकती हैं, जिन्होंने बासेल-II करार में निर्धारित पर्यवेक्षी मानकों का पालन किया हो। यह अपेक्षा बैंकों की आंतरिक श्रेणी-निर्धारण व्यवस्था को और अधिक महत्वपूर्ण बना देती है।

विदेशी मुद्रा विनिमय

ब्रिटिश पौंड (GBP) और कनाडाई डालर के सिक्कों (CAD) के मुंहबोले नाम 'केबल' और 'लूनी'

28 मई, 2010 को देश की विदेशी मुद्रा की आरक्षित निधि 271 बिलियन अमरीकी डालर थी।

जिंस (पण्य) बाज़ार

सावरिन जोखिम के समक्ष बचाव ने सोने को प्रति औंस 1,180डालर तक पहुंचाया

सोने की कीमतें यूरोप में बढ़ कर प्रति औंस 1,180 डालर तक पहुंच गईं तथा यूरो और स्विस फ्रैंक में रिकार्ड स्तर तक अधिक हो गईं, क्योंकि निवेशक इस आशंका के प्रति चिंतित हैं कि ग्रीक -शैली की ऋण समस्या यूरो जोन में अन्यत्र भी फैल सकती है। सावरिन जोखिम तथा उसके फलस्वरूप विदेशी मुद्रा बाज़ार में निर्मित होने वाली अस्थिरता के समक्ष बचाव के रूप में सोना अधिकाधिक आकर्षक होता जा रहा है। हाजिर (spot) सोने की बोली न्यूयार्क में विलंबित 1,174 .20 डालर के विरुद्ध 1,177.25 डालर प्रति औंस लगाई गई। बाज़ार में क्रीत-बिक्रीत सोने पर आधारित विश्व की सबसे बड़ी निधि, न्यूयार्क के एसपीडीआर गोल्ड ट्रस्ट द्वारा उसकी धारिता में 7 टन की वृद्धि के साथ धारिता के 1,166.002 टन के रिकार्ड स्तर तक पहुंच जाने की रिपोर्ट दिए जाने के फलस्वरूप बुलियन की निवेशपरक मांग जोरदार रही।

पूंजी बाज़ार

बॉण्डों द्वारा उत्तम कार्य-निष्पादन

हाल के महीनों में सरकारी बॉण्डों में सबसे अच्छी तेजी की स्थिति परिलक्षित हुई। इस उम्मीद में कि विद्यमान यूरोपीय संकट द्वारा चकनाचूर विदेशी निधियां भारतीय आस्तियों में धन लगाना जारी रखेंगी, जब शेयरों में गिरावट की प्रवृत्ति शुरू हुई, तो व्यापारी ऋणों की सुरक्षा में जुट गए। प्रतिफल में कमी से न केवल निवेशकों, अपितु सरकार को भी सहायता प्राप्त होती है, क्योंकि वह उसकी बाज़ार से उधार की लागत में कमी ला देती है। व्यापारी इस तेजी को प्रभावशाली बता रहे हैं, क्योंकि भारतीय समाशोधन निगम के अनुसार यह सभी बॉण्डों को एक साथ मिला देने पर लगभग 17,500 करोड़ रुपये के भारी परिमाण में प्रकट हुई।

बैंक अन्तरपणन से मुद्रा की क्रय-विक्रय दरों मे कमी

बैंकों द्वारा अन्तरपणन से शेयर बाज़ार में खरीदे -बेचे जाने वाले मुद्रा वायदों और काउंटर पर (OTC) लेनदेन किए जाने वाले वायदों के बीच अंतर कम हो गया है। वायदों (Futures) में डालर-रुपया दर और काउंटर पर वायदा लेनदेन बाज़ार के बीच अंतर 18 माह पहले के 26 पैसे से घट कर लगभग 3 पैसे हो गया है। यद्यपि मुद्रा वायदों में परिमाण खुदरा निवेशकों द्वारा प्रेरित होता है, जिनकी हिस्सेदारी 7-8 बिलियन डालर प्रतिदिन के परिमाण में लगभग 70-80 प्रतिशत होती है, तथापि वह बैंक ही हैं, जो दोनों ही बाज़ारों में टांगें फैलाने में तथा अन्तरपणन के माध्यम से लाभ कमाने में समर्थ होते हैं। कुशल बाज़ार की परिकल्पना यहीं चरितार्थ होती है। जब कभी अन्तरपणन का अवसर आएगा, बाज़ार में मुद्रा यह सुनिश्चित करते हुए प्रवाहित होगी कि कुछ समय बाद अंतर समाप्त हो जाए।

पारस्परिक निधियां

स्थानांतरित पारस्परिक निधि खातों के लिए शून्य ट्रायल कमीशन

भारतीय पारस्परिक निधि संघ (AMFI) के मुख्य कार्यपालक श्री एच. एन. सिनोर द्वारा यथा वर्णित भारतीय पारस्परिक निधि संघ ने ऐसे ग्राहकों से ट्रायल कमीशन लिये जाने पर रोक लगा दी है, जिन्होंने अपने खाते को किसी अन्य वितरक को स्थानांतरित कर दिया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा ग्राहकों को वर्तमान वितरक से अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिना ही वितरक बदलने की अनुमति दिए जाने के बाद इस प्रकार के अनुरोधों में तीव्र वृद्धि हुई है। अब निधि गृहों को पुराने या नये वितरक को ट्रायल कमीशन का भुगतान करना जरूरी नहीं है। इसके बजाय उक्त रकम एक अलग खाते में रखी जानी चाहिए तथा उसका उपयोग निवेशक शिक्षण के लिए किया जाना चाहिए।

बीमा

बैंकों को एक से अधिक बीमा ब्रॉण्ड बेचने का अवसर मिलेगा

बैंकों को एक से अधिक कम्पनी के बीमा उत्पादों को बेचने की अनुमति दी जा सकती है -यह एक ऐसा उपाय है, जो बीमा कम्पनियों की उनकी व्याप्ति बढ़ाने और लागत घटाने में सहायता कर सकता है। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) के अध्यक्ष श्री हरि नारायण ने वित्त मंत्रालय से मानदंडों को सरल बनाने तथा मामले को भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ उठाने का अनुरोध किया है। इस समय बैंकों को जीवन और सामान्य खण्डों में से प्रत्येक में एक कम्पनी के बीमा उत्पादों को बेचने की अनुमति है।

बीमाकर्ताओं में बदलाव

स्वास्थ्य बीमा में सुवाह्यता के शीघ्र ही वास्तविकता में परिणत हो जाने की संभावना है। सामान्य बीमा परिषद ने स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा के लिए अपना संशोधित आरूप हाल ही में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) को प्रस्तुत कर दिया है। बीमाकर्ता इस सुरक्षा को खरीद लेने पर उन्हीं सुविधाओं को प्रतिधारित करते हुए स्वास्थ्य सुरक्षा बेचने में समर्थ होंगे। सिद्धान्तत: किसी सुवाह्य स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी से आशय है स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदाताओं को अपनी इच्छा के अनुरूप बादलने की योग्यता, तथापि उपचित बोनसों को बनाए रखना तथा पूर्ववर्ती बीमारियों को सुरक्षित करवाना।

अंतरराष्ट्रीय समाचार

कमजोर यूरो के कारण विदेशी मुद्रा की आरक्षित निधि घट कर 3.4 बिलियन डालर हुई

7 मई तक के सप्ताह में भारत की विदेशी मुद्रा की आरक्षित निधि 3.39 बिलियन डालर घट कर 276.24 बिलियन डालर रह गई, क्योंकि निवेशक ग्रीस में उत्पन्न सावरिन ऋण संकट से पिटे यूरो से भयभीत हो गए। यूरो के कमजोर पड़ने का परिणाम देश की डालरेतर मूल्यवर्गित आरक्षित निधि के मूल्य में कमी के रूप में सामने आया, जिनके कुल विदेशी मुद्रा भंडार के लगभग 25 % होने का अनुमान है। 23 जनवरी, 2009 के बाद आरक्षित निधि में आई यह सबसे तीव्र गिरावट है। 7 मई तक के सप्ताह में डालर में आई 0.78 % की गिरावट के समक्ष यूरों में 2.63 % की गिरावट आई। इसी अवधि में डालर के समक्ष रुपया 44.54 से घट कर 45.4 पर आ गया।

अनिश्चित समय में अमरीकी कोषागार अपेक्षाकृत सुरक्षित दांव

यूरो क्षेत्र में व्याप्त संकट के बीच विश्वभर के केन्द्रीय बैंक अमरीकी सरकारी बॉण्डों या कोषागार में निवेश करते हुए डालर की ओर एकत्रित हो गए हैं, जिससे ग्रीनबैक से बाहर निकलने की चार माह पुरानी प्रवृत्ति

बदल गई है। विश्वभर के केन्द्रीय बैंकों ने अमरीकी सरकार के बॉण्डों में अपने निवेश (exposures) फरवरी के 2,676.5 बिलियन डालर से बढ़ा कर मार्च में 2,708.8 बिलियन डालर कर दिया है। कारपोरेट और वाणिज्यिक बैंकों जैसी अन्य संस्थाओं द्वारा किए गए निवेशों सहित कोषागार की कुल विदेशी धारिताएं लगभग 3.5 % बढ़ कर मई के 3752.2 बिलियन डालर के स्थान पर मार्च में 3884.6 बिलियन डालर हो गईं। सितम्बर, 2008 में लेहमान ब्रदर्स की विफलता के बाद गहराए सब-प्राइम संकट के बाद यह धारिताओं में हुई सर्वाधिक मासिक वृद्धि है।

यूरोप पुन: ध्यान का केन्द्र बना

ग्रीस के सार्वजनिक वित्त द्वारा यूरो क्षेत्र को तूफान के बीच ला खड़ा कर देने से सम्बन्धित कठिनाई के परिणामस्वरूप वैश्विक वित्तीय बाज़ार का सम्पूर्ण ध्यान अब यूरोप की ओर केन्द्रित हो गया है। ऋण की दृष्टि से ग्रीस की स्थिति शेष अधिकांश यूरोक्षेत्र की स्थिति से बहुत अधिक भिन्न नहीं है। यहां तक कि इटली और बेल्जियम के ऋण भी उनके सम्बन्धित सकल घरेलू उत्पाद के 100 % से अधिक हैं। इन ऋणों की औसत परिपक्वता अवधि भी पांच और सात वर्षों के बीच होते हुए महत्वपूर्ण रूप से भिन्न नहीं है। हालांकि, जहां तक बाज़ार का सम्बन्ध है, इस 'समूह वाले मामलों' को शेष मामलों से अलग कर देने वाली विशेषता है ऋणों और घाटे (निजी ऋण भी) का संयोजन।

विशिष्ट घटनाएं

बैंकों को ऋण देने के पहले भवन के पूर्ववृत्त की जांच कर लेनी चाहिए : राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

नये मकान निर्मित करते समय आपदा प्रतिरोधी अनुपालन उपाय कार्यान्वित किए जाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (NDMA) ने भारतीय रिज़र्व बैंक को सुझाव दिया है कि वह एक ऐसी नीति बनाए जिसमें बैंकों के लिए यह आवश्यक हो कि वे मकान-निर्माण के लिए ऋण प्रदान करने से पहले निर्माण के पूर्ववृत्त की जांच कर लें। श्री एन.सी. विज़, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का कहना है कि "कई एक स्थान भूकंप प्रवण क्षेत्रों में हैं तथा ऐसे क्षेत्रों में किसी नये निर्माण को उसका प्रतिरोध करने में सक्षम होना चाहिए। इसे प्राप्त करने के लिए हमने भारतीय रिज़र्व बैंक को यह समझा दिया है कि वह एक ऐसी नीति बनाए जिसमें बैंकों के लिए यह आवश्यक हो कि आवास ऋण प्रदान करने वाले बैंकों को यह भी देखना चाहिए कि सभी उधारकर्ताओं ने आपदा प्रतिरोधी मकान रखने के लिए अपेक्षित उपायों का पालन किया है।"

ऋण प्रतिभूतिकरण बाज़ार में गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों का अभ्युदय

गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों ने वर्ष 2009-10 में सुनियोजित वित्त बाज़ार में अपनी उपस्थिति बढ़ा ली है। जहां भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों से निरुद्ध बैंक पीछे रह गए, वहीं पिछले वर्ष ऋण वातावरण में हुए सुधार ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के लिए सुनियोजित ऋणों की मात्रा बढ़ाना आसान कर दिया। दूसरी ओर, बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रतिभूतिकरण सम्बन्धी मानदंडों को कठोर बनाने की तैयारी किए जाने के परिणामस्वरूप सुनियोजित वित्त बाज़ार में उनके अंश में और भी कमी आने की आशा करते हैं। भारतीय निवेश सूचना और साख निर्धारण एजेन्सी (ICRA) नामक साख निर्धारण एजेन्सी द्वारा लगाए गए अनुमानों के अनुसार वर्ष 2009-10 में प्रतिभूतिकरण बाज़ार में सर्वाधिक बड़ी कम्पनी थी वाणिज्यिक वाहन उधारदाता श्रीराम ट्रासंपोर्ट फाइनैन्स। इसने वर्ष 2009-10 में 8,750 करोड़ रुपये मूल्य के ऋणों को प्रतिभूत किया। प्रयुक्त वाणिज्यिक वाहनों के लिए ऋणों में विशेषज्ञता रखने वाली इस कम्पनी ने वर्ष 2008-09 में 3000 करोड़ रुपये मूल्य के ऋणों को प्रतिभूत किया था।

नयी नियुक्तियां

पीएफआरडीए के अध्यक्ष

केन्द्र ने आईडीबीआई बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक क्षी योगेश अग्रवाल को पांच वर्ष की अवधि के लिए अंतरिम पेंशन निधि विनियामक प्राधिकरण (PFRDA) के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है।

सेबी के कार्यपालक निदेशक

श्री अजांत बरुआ को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) का कार्यपालक निदेशक नियुक्त किया गया है। इसके पूर्व वह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में विधिक मामला विभाग में विधिक सलाहकार थे।

उत्पाद एवं गंठजोड़

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा बिक्री केन्द्रों के लिए संयुक्त उद्यम का गठन

भारतीय स्टेट बैंक ने छ: लाख बिक्री केन्द्र (POS) टर्मिनलों - क्रेडिट और डेबिट कार्डों के माध्यम से भुगतान पंजीकृत करने हेतु स्वाइप मशीनों- की स्थापना करने के लिए संयुक्त उद्यम (JV) के भागीदारों के रूप में वीसा इंटरनेशनल और इलैवॉन का चयन किया है। पिछले वर्ष आईसीआईसीआई ने अपने बिक्री केन्द्र टर्मिनल नेटवर्क 80 मिलियन डालर (लगभग 365 करोड़ रुपये) में फर्स्ट डाटा कार्पोरेशन को बेच दिए थे। आईसीआईसीआई बैंक सर्वप्रथम शुरूआत करने वालों में से एक रहा है तथा उक्त बिक्री के समय

बैंक के पास 1,5 लाख मशीनों की संस्थापित क्षमता मौजूद थी। भारतीय स्टेट बैंक ने एसबीआई पेमेन्ट्स सर्विसेज के नाम से एक एक संयिक्त उद्यम निगमित किया है, जिसमें दोनों भागीदारों द्वारा महत्वपूर्ण प्रीमियम पर जोखिम उठाए जाएंगे।

बजाज एलाएंज ने देना बैंक के साथ गंठजोड़ किया

बजाज एलाएंज लाइफ इंश्योरेंस ने देना बैंक के साथ उसकी शाखाओं के माध्यम से बजाज एलाएंज समूह के जीवन बीमा उत्पादों 'सर्व शक्ति सुरक्षा' का वितरण करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है।

जेट एअरवेज़ का एसबीआई क्रेडिट कार्ड के साथ समझौता

जेट एअरवेज़ ने अपने अतिथियों को एक अनूठा यात्रा विकल्प उपलब्ध कराने के लिए भारतीय स्टेट बैंक और जी ई कैपिटल की संयुक्त सुविधा (offering) एसबीआई कार्ड के साथ गंठजोड़ किया है। इस व्यवस्था का उद्देश्य सम्पूर्ण भारत के अतिथियों के लिए हवाई यात्रा को अधिक वहनीय बनाना है। इस प्रस्ताव के अधीन एसबीआई क्रेडिट कार्डधारकों को jetairways.com पर उनकी टिकट खरीदी को छ: माह की अवधि सहित 0 % की समीकृत मासिक किश्त में परिवर्तित करने का विकल्प चुनने की सुविधा प्राप्त होगी।

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा मोबाइल फोन सेवा की शुरूआत

मोबाइल बैंकिंग सेवा की प्रायोगिक आधार पर सफलतापूर्व समाप्ति के बाद भारतीय स्टेट बैंक ने अंतत: अपनी मोबाइल बैंकिंग सेवा - 'स्टेट बैंक फ्रीडम' की शुरूआत कर दी है। इस नयी पहलकदमी के माध्यम से बैंक द्वारा प्रदान की जा रही कुछेक सेवाओं में फोन टॉप-अप और उयोगिता बिल का भुगतान शामिल हैं। इसके अलावा, किसी व्यक्ति के सेल-फोन के अनुप्रयोग-आधारित होने पर वह 50,000 रुपये तक की निधि अंतरित कर सकता है। अन्यथा उस व्यक्ति को केवल 1,000 रुपये तक की निधि अंतरित करने की सुविधा प्राप्त होगी। इस नयी पहलकदमी के माध्यम से उपलब्ध होने वाली कुछेक अन्य सुविधाओं में शेषराशि की जानकारी, पिछले पांच लेनदेनों के लघु (मिनी) विवरण, चेक पुस्तिका जारी किए जाने हेतु आदेश तथा बैंक के भीतर ही निधि अंतरण का समावेश है। यथा-सूचित रूप में बैंक रेलगाड़ी, एअरलाइन अथवा यहां तक कि चलचित्र के भी टिकटों की खरीद जैसी कुछेक अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु 'ग्राहक' के साथ बातचीत कर रहा है।

एसएसएलएल, एसबीआई के बीच कृषि ऋण देने हेतु समझौता

कृषि-सुप्रचालनिक कम्पनी श्री शुभम लॉजिस्टिक्स (Logistics) ने किसानों को गोदाम रसीदों पर ऋण प्रदान करने हेतु भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक समझौता किया है। किसान अपनी उपज की मज़बूरन बिक्री करने से बचने के लिए उसे श्री शुभम लॉजिस्टिक्स लिमिटेड द्वारा स्वाधिकृत और नियंत्रित गोदामों में

रख कर उपजोत्तर ऋण सुविधाओं की प्राप्ति सुनिश्चित कर सकते हैं तथा इन रसीदों पर भारतीय स्टेट बैंक से ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

वित्तीय क्षेत्र की मूलभूत जानकारी

निक्षेपागार अंतरण जांच

किसी निर्दिष्ट वसूलीकर्ता बैंकर द्वारा किसी निगम की विविध स्थानों से प्राप्तियों को जमा करने हेतु प्रयुक्त एक जांच। निक्षेपागार अंतरण जांच उन कम्पनियों के लिए, जो कई एक स्थानों से नकदी एकत्रित करती हैं, बेहतर नकदी प्रबन्धन सुनिश्चत करने की एक विधि है। एक अन्य पक्षकार सूचना सेवा पहले प्रत्येक स्थान के सुविधा प्रबन्धक से प्राप्त उस दिन की प्राप्तियों से सम्बन्धित आंकड़ों को संकेन्द्रण (concentration) बैंक को अग्रेषित करता है। इसके बाद संकेन्द्रण बैंक इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक जमा केन्द्र के लिए निक्षेपागार अंतरण जांच तैयार करता है और उन्हें जांच-संसाधन प्रणाली में दर्ज करता है। निक्षेपागार अंतरण जांच को "निक्षेपागार अंतरण प्रारूप" के रूप में भी जाना जाता है।

शब्दावली

वाणिज्यिक पत्र

वाणिज्यिक पत्र अल्पावधिक ऋण लिखत होते हैं, जो कारपोरेटों (कम्पनियों) द्वारा संस्थागत निवेशकों को विशिष्ट रूप से प्राप्य लेखों, मालसूची (स्टॉक) तथा अल्पावधिक देयताओं को पूरा करने के लिए जारी किए जाते हैं। इनकी अवधि सात दिन से ले कर एक वर्ष तक की भी हो सकती है। विशिष्ट रूप से, वाणिज्यिक पत्र उस समय अधिक लोकप्रिय हो सकते हैं, जब बाज़ार में निधियों का बाहुल्य हो तथा संस्थागत निवेशक अल्पावधिक धन को अभिनियोजित करने के अवसरों की तलाश में हों। निवेशकों के परिप्रेक्ष्य से वाणिज्यिक पत्र अनिरुद्ध (liquid) लिखत होते हैं, क्योंकि उनका गौण बाज़ार में लेनदेन किया जा सकता है। यह ऋण आम तौर पर बट्टे पर जारी किया जाता है, जिसमें प्रचलित बाज़ार दरों का निरूपण होता है।

प्रत्यावर्ती बंधक

बंधक का वह प्रकार, जिसमें मकान का स्वामी /स्वामिनी अपने मकान के मूल्य पर धन उधार ले सकता है। जब तक कि उधारकर्ता की मृत्यु नहीं हो जाती अथवा मकान बेचा नहीं जाता, उक्त बंधक (मूलधन या ब्याज) की चुकौती आवश्यक नहीं होती। प्रारंभिक बंधक रकम, उस दर, जिस पर ब्याज उपचित होता है, ऋण की अवधि तथा मकान की कीमत में बढ़ोत्तरी की दर को हिसाब में लेने के बाद लेनदेन संरचित किया

जाता है, ताकि ऋण की रकम ऋण के जीवनकाल की तुलना में मकान के मूल्य से अधिक न हो। प्राय: उधारदाता द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि उस मकान पर कोई अन्य धारणाधिकार न हो। किसी भी मौजूदा धारणाधिकार की प्रत्यावर्ती बंधक से प्राप्त होने वाली रकम से चुकौती अवश्य कर दी जानी चाहिए।

बाज़ार की खबरें

भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दर

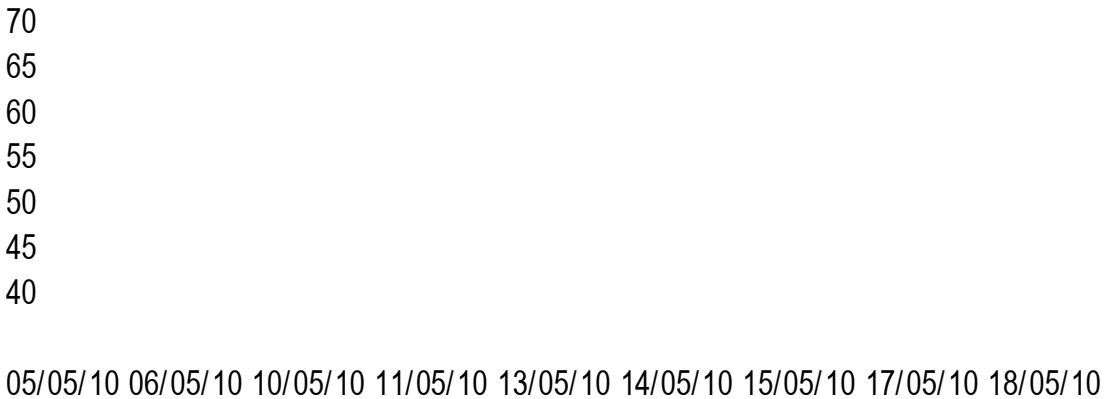

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

भारित औसत मांग दर

03/05/10 04/05/10 05/05/10 07/05/10 08/05/10 10/05/10 14/05/10 15/05/10 18/05/10 19/05/10 20/05/10 21/05/10 22/05/10 24/05/10 25/05/10 26/05/10 28/05/10

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड न्यूज़लेटर्स, मई, 2010

विनिमय दर

अमरीकी डालर / भारतीय रुपया नियत एवं अंतिम

47.00
46.50
46.00
45.50
44.50
44.00
43.50

पूर्वान्ह 11.30 बजे
अपरान्ह 5.00 बजे

03-05-10 17-05-10 31-05-10

स्रोत : भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (FEDAI)

भारत के समाचार पत्र पंजीकार (रजिस्ट्रार) के पास संख्या : 69228 / 98 के अधीन पंजीकृत

- पंजीकरण संख्या : एमएच / एमआर / दक्षिण -42 / 2010 -12
  पूर्व-अदायगी के बिना प्रेषित करने का लाइसेंस संख्या 15 / दक्षिण / 2010 -

- मुंबई पत्रिका चैनल छंटाई कार्यालय मुंबई - 1 पर प्रत्येक महीने की 25वीं और 26वीं तारीख को प्रेषित करें।

संस्थान समाचार

सीएआईआईबी परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

संस्थान दिसंम्बर, 2010 और उसके बाद से सीएआईआईबी परीक्षा के लिए आशोधित रूपरेखा को कार्यान्वित करेगा। इस उद्देश्य के लिए संस्थान ने अपने सभी हितधारकों से परामर्श करते हुए सीएआईआईबी परीक्षा के पाठ्यक्रम को सशोधित एवं पुनर्संरचित कर दिया है।

संशोधित (2010) पाठ्यक्रम

नई सीएआईआईबी परीक्षा के अभ्यर्थियों को दो अनिवार्य प्रश्नपत्र और एक वैकल्पिक प्रश्नपत्र लिखने होंगे। अनिवार्य प्रश्नपत्र एवं चयनात्मक प्रश्नपत्र की सूची इसके नीचे दी गई है। ग्यारह चयनात्मक प्रश्नपत्रों में से अभ्यर्थी को एक चयनात्मक प्रश्नपत्र को चुनना होगा।

I अनिवार्य प्रश्नपत्र

1. उन्नत बैंक प्रबन्धन
2. बैंक : वित्तीय प्रबन्धन

II. वैकल्पिक प्रश्नपत्र

1. कारपोरेट बैंकिंग
2. ग्रामीण बैंकिंग
3. अन्तरराष्ट्रीय बैंकिंग
4. खुदरा (रिटेल) बैंकिंग
5. सहकारी बैंकिंग
6. वित्तीय परामर्शन
7. मानव संसाधन प्रबन्धन
8. सूचना प्रौद्योगिकी
9. जोखिम प्रबन्धन
10. केन्द्रीय बैंकिंग
11. खज़ाना (ट्रेज़री) प्रबन्धन

पाठ्यक्रम की विषयवस्तु सावधानीपूर्वक तैयार की गई है, ताकि वह विशेषत: विषम स्तर पर आधारित बैंकिंग परिचालनों के युग में आधुनिक बैंकिंग के कार्यात्मक-परिवेश तथा बैंकों के एसबीयूस (SBUs) से प्रासंगिक हो।

पाठ्यक्रम एवं पाठ्यक्रम की विषयवस्तु, परीक्षा के नियमों से सम्बन्धित विवरण http: / / www.iibf.org.in पर देखे जा सकते हैं।

अनिवार्य और चयनात्मक विषयों की पाठ्यसामग्री मुद्रणाधीन है तथा वह जुलाई, 2010 के अंत तक प्रकाशित होगी। उक्त पाठ्यसाग्री का हिन्दी में अनुवाद कार्य प्रगति पर है तथा उचित समय पर अभ्यर्थीगण उसे संस्थान के पोर्टल से डाउनलोड कर सकेंगे।

जनवरी 2010 की परीक्षा

संशोधित पाठ्यक्रम दिसम्बर 2010 / जनवरी 2011 की परीक्षा से लागू किया जा रहा है। अतएव (क) सीएआईआईबी परीक्षा के लिए पहली बार नाम दर्ज कराने वाले अभ्यर्थियों और (ख) सीएआईआईबी परीक्षा के लिए नाम दर्ज कराने के इच्छुक अर्थात् चार (4) अनुमेय क्रमिक प्रयासों की सुविधा का उपयोग कर लेने के उपरांत तथा परीक्षा उत्तीर्ण न कर पाने वाले अभ्यर्थियों, दोनों ही को अपने आवेदन संशोधित (2010) पाठ्यक्रम के तहत प्रस्तुत करने होंगे। ये अभ्यर्थी पूर्ववर्ती पाठ्यक्रम के तहत परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर सकते। वास्तव में संस्थान पुराने प्रतिमान के अधीन कोई आवेदन नहीं स्वीकार करेगा। तदनुसार पुराने प्रतिमान वाली परीक्षा दिसम्बर, 2011 के बाद अस्तित्व में नहीं रहेगी।

यह सिफ़ारिश की जाती है कि ऐसे अभ्यर्थियों को, जिन्होंने दिसम्बर, 2009 की सीएआईआईबी परीक्षा हेतु नाम दर्ज करवाया था तथा जून, 2010 में सीएआईआईबी परीक्षा में अब तक किसी भी प्रश्नपत्र में उत्तीर्ण हुए बिना दो प्रयास कर चुके हैं, को पुराने पाठ्यक्रम के तहत दो प्रयासों के दूसरे खंड (ब्लॉक) के लिए नाम दर्ज करवाने के बजाय नये पाठ्यक्रम के तहत आवेदन करने पर विचार करना चाहिए।

पुराने पाठ्यक्रम के तहत सीएआईआईबी परीक्षा के लिए पहले से नाम दर्ज करवा चुके अभ्यर्थियों के लिए :

-परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु चार क्रमिक प्रयासों की वर्तमान समय-सीमा जारी रहेगी।

-हालांकि, अभ्यर्थीगण चार (4) अनुमेय क्रमिक प्रयासों की सुविधा का लाभ उठाने के पहले भी संशोधित पाठ्यक्रम को अपना सकते हैं।

-अभ्यर्थियों को पुराने पाठ्यक्रम के तहत उत्तीर्ण विषय / यों यदि कोई हो, के लिए कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि पाठ्यक्रम पूरी तरह पुनरीक्षित और पुनर्संरचित कर दिया गया है।

-नवम्बर, 2010 से पुराने पाठ्यक्रम के लिए किसी भी नये अभ्यर्थी का नाम नहीं दर्ज किया जाएगा। नये अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक रूप से केवल संशोधित पाठ्यक्रम हेतु ही नाम दर्ज करवाना होगा।

जिन्होंने पहले ही सीएआईआईबी उत्तीर्ण कर ली है, उनके लिए

निरंतर व्यावसायिक विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से ऐसे अभ्यर्थी, जो पहले से सीएआईआईबी हैं, अपनी पसंद के चयनात्मक विषयों की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। उस विषय की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर उक्त अभ्यर्थी को उस विशिष्ट चयनात्मक विषय पर सीएआईआईबी के पश्चात् वाली योग्यता का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। हालांकि, चूंकि सभी चयनात्मक प्रश्नपत्रों की परीक्षा एक-साथ संचालित होगी, अभ्यर्थीगण एक बार में केवल एक ही चयनात्मक प्रश्नपत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। कुछ समय के बाद संस्थान ऐसी अतिरिक्त अर्हताओं को अभ्यर्थियों को अपनी सहयोगी सदस्यता (Associate membership) प्रदान किए जाने हेतु सम्बद्ध करेगा।

पाठ्यक्रम, आवेदन पत्र और परीक्षा की तिथियों आदि से सम्बन्धित विवरण के लिए http : / / www.iibf.org.in. देखें।

परियोजना वित्त में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

23 अगस्त से 28 अगस्त, 2010 तक आईएफएमआर कैम्पस, चेन्नै में आयोजित होने वाले परियोजना वित्त में प्रमाण पत्र के 11 वें बैच के लिए नामांकन का कार्य जारी है (विवरण के लिए वेबसाइट www.iibf.org.in. देखें)।

माइक्रो एवं माइक्रो शोध :

माइक्रो एवं माइक्रो शोध प्रस्ताव आमंत्रित हैं। विवरण के लिए वेबसाइट www.iibf.org.in. देखें)।

श्री आर. भास्करन द्वारा मुद्रित, श्री आर. भास्करन द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा क्वालिटी प्रिंटर्स (I) , 6 - बी मोहता भवन, 3री मंजिल, डॉ. ई. मोज़ेस मार्ग, वर्ली, मुंबई - 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स, 'दि आर्केड', विश्व व्यापार केन्द्र, 2री मंजिल, पूव स्कंध, कफ परेड, मुंबई - 400 005 से प्रकाशित।

संपादक : श्री आर. भास्करन

सेवा में

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स
दि आर्केड, विश्व व्यापार केन्द्र, 2री मंजिल, पूर्व खण्ड, कफ परेड,
मुंबई - 400 005
टेलीफोन : 2218 7003 / 04 / 05 फैक्स : 91-22-2218 5147 / 2215 5093
तार : INSTIEXAM ई-मेल : iibgen@bom5 vsnl.net.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in.

आईआईबीएफ विज़न जून, 2010